Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
(A National bi-lingual Quarterly Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal)
ISSN : 2395-7069(Print), Impact Factor: (Cosmos 7.650 & I2OR 5.120), Volume 12, No. 04, October-December, 2026, pp. 101-108

बिहार में ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता: NFHS–4 और NFHS–5 के आधार पर एक विश्लेषण

कल्याणी प्रियदर्शनी[1*] एवं प्रो. रति कांत दाश[2]

[1]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार।
[2]प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, जगजीवन कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार।

[*]Corresponding Author: prydarshnikalyani@gmail.com

Citation: *प्रियदर्शनी, कल्याणी एवं दाश, रति (2026). बिहार में ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता: NFHS–4 और NFHS–5 के आधार पर एक विश्लेषण. Journal of Commerce, Economics & Computer Science, 12(04), 101–108.*

सार

बिहार में 15–49 वर्ष की जिन महिलाओं के पास ऐसा बैंक/बचत खाता है जिसे वे स्वयं उपयोग करती हैं, उनका हिस्सा 2015–16 के NFHS–4 में 26.4% था और 2019–20 के NFHS–5 में 76.7% हो गया (IIPS – ICF, 2020)। यह शोध–पत्र पूरी तरह द्वितीयक आँकड़ों NFHS–4 व NFHS–5 के राज्य और जिला–स्तरीय फैक्टशीट, जीविका के प्रतिवेदन, जन–धन योजना के सरकारी आँकड़े और विश्व बैंक के ळसवइंस थ्पदकम• विश्लेषण के आधार पर यह जाँचता है कि खाते तक यह पहुँच महिलाओं की वास्तविक आर्थिक स्वायत्तता में कितनी बदली। तीन निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, पहुँच लगभग बराबर हो गई है: ग्रामीण (76.2%) और शहरी (79.1%) महिलाओं के बीच अंतर केवल 2.9 प्रतिशत अंक रह गया। दूसरा, घरेलू निर्णयों में भागीदारी 75.2% से 86.5% और मोबाइल स्वामित्व 40.9% से 51.4% हुआ। तीसरा, आय और संपत्ति के संकेतक ठहरे रहे: नकद भुगतान वाला काम करने वाली महिलाएँ 12.5% से केवल 12.6% हुईं, और घर/ज़मीन पर महिलाओं का स्वामित्व 58.8% से घटकर 55.3% रह गया। जिला–स्तर पर नवादा में खाता–स्वामित्व 21.4% से 72.3% हुआ, पर सूक्ष्म–ऋण का उपयोग केवल 10.9% है। निष्कर्ष यह है कि बिहार में "खाता खुलने" का चरण काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है; अब चुनौती खाते के सक्रिय उपयोग, ऋण तक पहुँच, डिजिटल क्षमता और आय–अर्जन से उसके जुड़ाव की है।

शब्दकोश: *वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, बिहार,* NFHS, *प्रधानमंत्री जन–धन योजना, जीविका, नवादा।*

प्रस्तावना

वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि हर वयस्क विशेषकर गरीब, ग्रामीण और महिलाएँ बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान जैसी औपचारिक सेवाओं तक पहुँच सके और उनका वास्तव में उपयोग कर सके। भारत में इसका सबसे बड़ा कदम प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY, 2014) रही। 15 जनवरी 2025 तक इसके अंतर्गत 54.58 करोड़ खाते खुले, जिनमें 30.37 करोड़ (55.7%) महिलाओं के हैं (राज्य सभा, 2025)।

Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.

विश्व बैंक के Global Finde 2021 के अनुसार भारत में 78% वयस्कों के पास खाता है और 2011 में 22 प्रतिशत अंक का लैंगिक अंतर अब नगण्य रह गया है (World Bank Blog(World Bank] FindeÛ 2021)।

पर "खाता होना" और "खाते से सशक्त होना" अलग बातें हैं। उसी विश्लेषण के अनुसार खाताधारक महिलाओं में 42% के खाते निष्क्रिय हैं, जबकि पुरुषों में 30%; और औपचारिक कर्ज़दार महिलाएँ 10% हैं, जबकि पुरुष 15% (World Bank Blog)। पहुँच लगभग बराबर हो गई है, पर उपयोग और ऋण में अंतर बना है।

बिहार इस प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है। NFHS–4 (2015–16) में यहाँ केवल 26.4% महिलाओं के पास अपना उपयोग किया जाने वाला खाता था; NFHS–5 (2019–20) में 76.7% (IIPS – ICVF, 2020)। साथ ही, राज्य में जीविका के रूप में 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क है (BRLPS, 72वीं QPR, 2025)।

यह शोध–पत्र एक प्रश्न पूछता है: क्या खाते की यह छलाँग बिहार की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता निर्णय–क्षमता, आय, संपत्ति और डिजिटल क्षमताकृमें भी दिखती है? खंड 2 वैचारिक ढाँचा देता है, खंड 3 आँकड़े और पद्धति, खंड 4–6 राज्य व जिला (नवादा सहित) स्तर के निष्कर्ष, खंड 7 जीविका की भूमिका, खंड 8 NFHS–6 के राष्ट्रीय संकेत और बाधाएँ, और खंड 9 निष्कर्ष व सुझाव।

साहित्य समीक्षा एवं वैचारिक ढाँचा

अमर्त्य सेन (1999) विकास को लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और क्षमताओं के विस्तार के रूप में देखते हैं; आय या खाता साधन है, लक्ष्य नहीं। नाइला कबीर (1999) सशक्तिकरण को तीन परस्पर जुड़े आयामों में मापती हैं: संसाधन (भविष्य के चुनाव की पूर्व–शर्तें), एजेंसी (निर्णय लेने और उन पर अमल की क्षमता) और उपलब्धियाँ (उन चुनावों के परिणाम)। इस पत्र में बैंक खाता और मोबाइल "संसाधन" हैं, घरेलू निर्णयों में भागीदारी "एजेंसी" है, और नकद आय व संपत्ति "उपलब्धियाँ" हैं। तीनों के लिए NFHS में समान प्रश्न दो चक्रों में पूछे गए, इसलिए तुलना संभव है।

तालिका: कबीर का ढाँचा और NFHS संकेतक

कबीर का आयाम	इस पत्र का संकेतक (NFHS)
संसाधन	अपना बैंक/बचत खाता; अपना मोबाइल; इंटरनेट का उपयोग
एजेंसी	तीन घरेलू निर्णयों में भागीदारी
उपलब्धियाँ	नकद भुगतान वाला काम; घर/ज़मीन का स्वामित्व

पूर्व अध्ययनों से तीन बातें निकलती हैं। पहली, भारतीय स्वयं सहायता समूहों पर आधारित अध्ययन में समूह–सदस्यता और महिला सशक्तिकरण के बीच सकारात्मक संबंध पाया गया है (Swain और Wallentin, 2009)। दूसरी, बिहार के जीविका परिवारों के विश्व बैंक–समर्थित सर्वेक्षण के अनुसार सदस्य परिवारों में ऊँची लागत वाले कर्ज़ का बोझ कम है और ऋण–ढाँचा बेहतर हुआ है (World Bank Data Catalog)। तीसरी, ORF का विश्लेषण दिखाता है कि भारत में खाते के प्रसार के बावजूद ऋण और डिजिटल उपयोग में लैंगिक अंतर बना है और केवल मोबाइल रखना वित्तीय उपयोग की गारंटी नहीं है (Kumar, ORF, 2023)। यह पत्र इन्हीं तीन बिंदुओं को बिहार और नवादा के आँकड़ों से परखता है।

उद्देश्य, आँकड़े और पद्धति

उद्देश्य

- बिहार में महिलाओं के बैंक खाते की पहुँच में NFHS–4 से NFHS–5 तक के बदलाव को मापना।

- पहुँच के साथ एजेंसी (निर्णय, मोबाइल, इंटरनेट) और उपलब्धि (आय, संपत्ति) संकेतकों की तुलना करना।
- बैंक–खाता और सूक्ष्म–ऋण के संदर्भ में नवादा का स्थान बिहार के अन्य जिलों की तुलना में निर्धारित करना।
- जीविका के आँकड़ों से देखना कि समूह–ढाँचा खाते से ऋण तक की कड़ी कैसे बनाता है।

आँकड़ों के स्रोत

स्रोत	उपयोग
NFHS-5 बिहार राज्य फैक्टशीट (IIPS & ICF, 2020)	राज्य के संकेतक, NFHS-4 से तुलना; शहरी/ग्रामीण विभाजन
IIPS के जिला-स्तरीय मॉडल-आधारित अनुमान	खाता-स्वामित्व, सूक्ष्म-ऋण की जानकारी व उपयोग: 38 जिले
NFHS-5 बिहार राज्य रिपोर्ट (DHS Program)	मोबाइल से वित्तीय लेन-देन, महिला रोज़गार
जीविका QPR व वार्षिक रिपोर्ट	SHG, बीमा, बैंक-ऋण के आँकड़े
राज्य सभा उत्तर, PIB, World Bank, ORF	राष्ट्रीय संदर्भ, Findex
NFHS-6 की PIB विज्ञप्ति	नवीनतम राष्ट्रीय संकेत

पद्धति (सरल शब्दों में)। विश्लेषण वर्णनात्मक हैः प्रतिशत की दो चक्रों में तुलना और परिवर्तन की गणना। प्रतिशत अंक का अर्थ दो प्रतिशतों का सीधा अंतर है (जैसे 26.4% से 76.7% = 50.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि)। जिला–स्तर के आँकड़े मॉडल–आधारित अनुमान हैंः हर जिले में सीधे बहुत कम महिलाओं से पूछा जा सकता है, इसलिए सांख्यिकीय विधि से राज्य–स्तरीय सर्वे को जिलों में बाँटकर अनुमान निकाले गए हैं; वे सटीक गिनती नहीं, विश्वसनीय अनुमान हैं। तुलना की वैधता के लिए दोनों चक्रों में खाते का प्रश्न एक हैः "क्या आपके पास ऐसा बैंक या बचत खाता है जिसे आप स्वयं उपयोग करती हैं?" (World Bank Microdata Library)। NFHS–5 बिहार के लिए 35,834 परिवारों और 42,483 महिलाओं का सर्वे है (IIPS – ICF, 2020); NFHS–4 बिहार में 36,772 परिवार और 45,812 महिलाएँ शामिल थीं (IIPS, 2017)।

दायरा। ये आँकड़े संबंध दिखाते हैं, कारण सिद्ध नहीं करतेः यह नहीं कहा जा सकता कि केवल जन–धन या जीविका से ही सब बदलाव आया। निष्कर्ष इसी सीमा में पढ़े जाएँ।

बैंक खाताः पहुँच में परिवर्तन

तालिका 1 बिहार की 15–49 वर्ष की महिलाओं के प्रमुख संकेतक दोनों चक्रों में दिखाती है।

तालिका 1: बिहार में महिलाओं के संकेतक (%), NFHS–4 (2015–16) बनाम NFHS–5 (2019–20)

संकेतक	NFHS-4 कुल	NFHS-5 शहरी	NFHS-5 ग्रामीण	NFHS-5 कुल	परिवर्तन (प्रतिशत अंक)
अपना बैंक/बचत खाता	26.4	79.1	76.2	76.7	+50.3
अपना मोबाइल फ़ोन	40.9	61.8	49.3	51.4	+10.5
तीन घरेलू निर्णयों में भागीदारी (विवाहित)	75.2	84.0	87.0	86.5	+11.3
नकद भुगतान वाला काम (पिछले 12 माह)	12.5	11.7	12.8	12.6	+0.1
घर और/या ज़मीन का स्वामित्व	58.8	53.4	55.7	55.3	−3.5
10 या अधिक वर्ष की शिक्षा	22.8	48.0	25.2	28.8	+6.0

स्रोतः IIPS - ICF (2020), NFHS–5 बिहार राज्य फैक्टशीट; परिवर्तन लेखक की गणना।

खाते का संकेतक सबसे नाटकीय हैः बिहार में 50.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि (लगभग तीन गुना; लेखक की गणना)। राष्ट्रीय स्तर पर यही हिस्सा 53% से 78.6% हुआ (Kumar, ORF, 2023; PIB, 2026), यानी बिहार

बहुत पीछे से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर के पास पहुँचा। सबसे उल्लेखनीय बात ग्रामीण–शहरी अंतर का सिमटना है: NFHS–5 में ग्रामीण 76.2% बनाम शहरी 79.1%।

NFHS के आँकड़े कारण नहीं बताते, पर नीतिगत संकेत स्पष्ट हैं: जन–धन का लक्ष्य "हर परिवार" से बदलकर "हर बिना–खाते का वयस्क" हुआ (राज्य सभा, 2025), जो परिवार के भीतर छूटी महिलाओं तक पहुँच बढ़ा सकता था। इसलिए यह उछाल कम से कम आंशिक रूप से योजना–प्रेरित होने की संभावना है।

पर खाता खुलना सक्रिय उपयोग का प्रमाण नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर 42% महिला खाताधारकों के खाते निष्क्रिय हैं (World Bank Blog), और सरकार के अनुसार जन–धन के लगभग 79% खाते ही चालू हैं (अक्टूबर 2024 की स्थिति; लोकसभा में सरकारी उत्तर)। यह राष्ट्रीय पैटर्न बिहार के लिए संदर्भ–संकेत है, मापा हुआ राज्य–तथ्य नहीं।

उपयोग और सशक्तिकरण संकेतक

एजेंसी: निर्णय–क्षमता। तीन घरेलू निर्णयों (अपने स्वास्थ्य, बड़ी घरेलू खरीद और मायके/रिश्तेदारों से मिलने) में भागीदारी 75.2% से 86.5% हुई। ग्रामीण महिलाएँ (87.0%) शहरी (84.0%) से आगे हैं। राष्ट्रीय औसत 88.7% है (CGI साओ पाउलो, NFHS–6 सारांश), यानी बिहार अब उसके नज़दीक है। यह संकेतक भागीदारी मापता है, घर के पैसे पर स्वतंत्र नियंत्रण नहीं।

संसाधन: मोबाइल और इंटरनेट। मोबाइल स्वामित्व 40.9% से 51.4% हुआ, पर शहरी–ग्रामीण अंतर 12.5 प्रतिशत अंक है (61.8% बनाम 49.3%)। इंटरनेट का कभी उपयोग करने वाली महिलाएँ केवल 20.6% हैं; ग्रामीण 17.0% बनाम शहरी 38.4% (IIPS – ICF, 2020)। मोबाइल रखने वाली महिलाओं में भी केवल हर दसवीं उसे वित्तीय लेन–देन के लिए इस्तेमाल करती है (शहरी 13%, ग्रामीण 10%) (IIPS – ICF, राज्य रिपोर्ट)। यानी खाता तो है, पर डिजिटल रास्ते से उसका उपयोग बहुत सीमित है।

उपलब्धि: आय। नकद भुगतान वाला काम करने वाली महिलाएँ 12.5% से 12.6% पर लगभग स्थिर रहीं। राज्य रिपोर्ट के अनुसार 18% महिलाओं ने पिछले 12 महीने में कोई काम किया, यानी काम करने वाली लगभग हर तीन में से एक महिला को नकद भुगतान नहीं मिलता (12.6% बनाम 18%) (IIPS – ICF, राज्य रिपोर्ट)।

उपलब्धि: संपत्ति। घर/ज़मीन पर महिलाओं का स्वामित्व 58.8% से घटकर 55.3% रहा।

निष्कर्ष। कबीर के ढाँचे में "संसाधन" का पहला हिस्सा (खाता) सबसे तेज़ी से बना, "एजेंसी" मध्यम गति से बढ़ी, और "उपलब्धियाँ" (नकद आय, संपत्ति) नहीं बदलीं। यही इन आँकड़ों की मुख्य सीख है: पहुँच बनी, आय नहीं।

जिला–स्तरीय चित्र: नवादा

नवादा का स्थान समझने के लिए IIPS के जिला–स्तरीय अनुमान (खाता–स्वामित्व, सूक्ष्म–ऋण की जानकारी और उपयोग) का प्रयोग किया गया है। तालिका 2 नवादा और कुछ तुलनात्मक जिलों को दिखाती है।

तालिका 2: चयनित जिलों में महिलाएँ (%), NFHS–4 → NFHS–5 (मॉडल–आधारित अनुमान)

जिला	अपना खाता	सूक्ष्म-ऋण की जानकारी	सूक्ष्म-ऋण का उपयोग
नवादा	21.4 → 72.3 (+50.9)	25.6 → 60.0 (+34.4)	3.4 → 10.9 (+7.5)
गया	22.7 → 76.5 (+53.8)	23.9 → 62.1 (+38.2)	3.1 → 13.9 (+10.8)
नालंदा	31.3 → 76.9 (+45.6)	31.8 → 58.4 (+26.6)	6.3 → 14.1 (+7.8)
शेखपुरा	28.2 → 77.9 (+49.7)	28.2 → 62.6 (+34.4)	3.5 → 18.2 (+14.7)
जमुई	26.4 → 79.9 (+53.5)	34.6 → 68.6 (+34.0)	5.7 → 20.9 (+15.2)

औरंगाबाद	29.0 → 70.7 (+41.7)	30.1 → 56.5 (+26.4)	4.5 → 11.0 (+6.5)
पटना	39.4 → 77.5 (+38.1)	40.7 → 60.3 (+19.6)	4.1 → 13.1 (+9.0)

स्रोतः IIPS, जिला–स्तरीय मॉडल–आधारित अनुमान, NFHS–4 व NFHS–5; कोष्ठक में प्रतिशत अंक का परिवर्तन लेखक की गणना।

तीन बातें उभरती हैं। पहली, NFHS–4 में नवादा (21.4%) बिहार के 38 जिलों में दूसरे सबसे निचले स्थान पर था (केवल दरभंगा, 19.7%, इससे नीचे)। दूसरी, NFHS–5 में नवादा (72.3%) अब भी निचले पाँच जिलों में है; औरंगाबाद (70.7%), भोजपुर (71.3%), बक्सर (71.6%) और मुंगेर (72.0%) उससे नीचे हैं, जबकि रोहतास 83.5% के साथ सबसे ऊपर है। यानी नवादा ने 50.9 प्रतिशत अंक की बड़ी बढ़त ली, पर अपनी सापेक्ष स्थिति लगभग नहीं बदली। तीसरी, सूक्ष्म–ऋण में अंतर और गहरा हैः नवादा में 60.0% महिलाएँ इसके बारे में जानती हैं, पर केवल 10.9% उपयोग करती हैं, यानी जानने वालों में मोटे तौर पर पाँच में से एक। उपयोग के मामले में नवादा बिहार के निचले पाँच जिलों में है, और जमुई (20.9%) या शेखपुरा (18.2%) के लगभग आधे पर।

इससे दो निष्कर्ष निकलते हैंः नवादा में जानकारी का स्तर (60.0%) जिलों की सामान्य सीमा (लगभग 53–69%) में है, इसलिए अंतर जानकारी का नहीं, उपयोग का है; और जमुई व शेखपुरा दिखाते हैं कि इसी राज्य–ढाँचे में उपयोग लगभग दोगुना हो सकता है। चूँकि ये अनुमान हैं, छोटे अंतर (1–2 प्रतिशत अंक) पर ज़ोर नहीं दिया गया है।

जीविका और स्वयं सहायता समूह की भूमिका

जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी) राज्य में खाते और ऋण के बीच की संस्थागत कड़ी है। सितंबर 2025 तक 11.40 लाख SHG, 73,515 ग्राम संगठन और 1,684 संकुल स्तरीय संघ बन चुके थे, और कुल लामबंदी 1.40 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुँची (BRLPS, 72वीं QPR, 2025)। मार्च 2016 में 4.70 लाख SHG और 57 लाख परिवार थे (BRLPS, वार्षिक रिपोर्ट 2015–16), मार्च 2020 में 9.48 लाख SHG (BRLPS, 50वीं QPR, 2020) और मार्च 2021 में 10.34 लाख SHG व 1.27 करोड़ परिवार (BRLPS, AAP 2022–23) थे। यानी NFHS–4 (2015–16) से NFHS–5 (2019–20) के बीच SHG की संख्या लगभग दोगुनी हुई। साथ ही बिहार सरकार के जीविका–पृष्ठ पर अब 11.82 लाख SHG व 1.80 करोड़ परिवार दर्ज हैं (बिहार सरकार, जीविका)। 72वीं फच्ट यह भी बताती है कि 80.52 लाख SHG सदस्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और 91.12 लाख सदस्य प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में नामांकित थे। जून 2025 में PMJJBY नामांकन 74.26 लाख था (BRLPS, 71वीं QPR, 2025), यानी एक तिमाही में 6.26 लाख की वृद्धि। 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट में SHG के बैंक ऋण–संपर्क का कुल मूल्य ₹55,576 करोड़ दर्ज है और 72.45 लाख सदस्य आयुष्मान भारत में नामांकित बताए गए हैं (BRLPS, वार्षिक रिपोर्ट 2024–25)।

इन आँकड़ों का अर्थ तीन स्तरों पर हैः

- बचत और सुरक्षाः समूह–बैठक, बैंक में समूह–खाता और बीमा–नामांकन खाते के नियमित उपयोग का संस्थागत आधार बन सकते हैं।
- ऋण की कड़ीः सूक्ष्म–ऋण का उपयोग बिहार के सभी 38 जिलों में बढ़ा है (IIPS अनुमान; तालिका 2 में नवादा 3.4% से 10.9%), जो SHG–बैंक संपर्क की उपस्थिति से मेल खाता है। इस मेल को कारण सिद्ध नहीं माना जा सकता।
- ऋण–संरचनाः विश्व बैंक–समर्थित सर्वेक्षण के अनुसार जीविका सदस्य परिवारों में ऊँची लागत का कर्ज़ कम है (World Bank Data Catalog)।

पर एक सीमा भी दर्ज है। उद्यम के लिए महिला–नेतृत्व वाला व्यक्तिगत वित्त (Women-Led Individual Financing) 2024–25 में केवल 4,453 SHG सदस्यों को बैंकों के माध्यम से स्वीकृत हुआ (BRLPS, वार्षिक रिपोर्ट 2024–25), जबकि सदस्य करोड़ों में हैं। समूह–ऋण ने पहुँच बनाई है, पर व्यक्तिगत उद्यम–ऋण, जो नकद आय पैदा करता है, अभी बहुत छोटे पैमाने पर है। यह तालिका 1 में नकद–आय के ठहराव की एक संभावित संस्थागत व्याख्या है।

NFHS–6 का संकेत और प्रमुख बाधाएँ

NFHS–6 (2023–24)। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके तथ्यपत्र मई 2026 में जारी किए (6.79 लाख परिवार, 715 जिले)। राष्ट्रीय स्तर पर अपना खाता उपयोग करने वाली महिलाएँ 78.6% से 89.0%, अपना मोबाइल रखने वाली 53.9% से 63.6%, और कभी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली 33.3% से 64.3% हुईं (PIB, 2026)। इसी समय तीन घरेलू निर्णयों में भागीदारी लगभग वहीं रही: 88.7% से 89.0% (CGI साओ पाउलो, NFHS–6 सारांश)।

यह इस पत्र के मूल निष्कर्ष से सुसंगत है: जब राष्ट्रीय स्तर पर खाता–पहुँच 89% तक पहुँची, तब निर्णय–भागीदारी लगभग नहीं बदली। पहुँच का सतत विस्तार एजेंसी और आय में अपने–आप नहीं बदलता।

प्रमुख बाधाएँ, जो ऊपर के साक्ष्य से निकलती हैं:

निष्क्रिय खाते: भारत में 42% महिला खाताधारकों के खाते निष्क्रिय हैं, पुरुषों में 30% (World Bank Blog)। भारत के लैंगिक अंतर में आई गिरावट का एक कारण पुरुषों के निष्क्रिय खातों का बंद होना भी है (Women's World Banking, 2022)।

ऋण में लैंगिक अंतर: महिला कर्ज़दार 10%, पुरुष 15%; महिलाओं को उनकी जमा–राशि के बराबर लगभग 27% ऋण मिलता है, पुरुषों को 52%; लगभग 90% महिला उद्यमियों ने औपचारिक वित्त नहीं लिया (World Bank Blog, 2020 के अध्ययन और IFC 2022 के हवाले से)।

सेवा–बिंदु पर महिलाओं की कमी: मार्च 2022 में 13 लाख बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट में 10% से कम महिलाएँ थीं (World Bank Blog)।

डिजिटल दूरी: बिहार में केवल हर दसवीं मोबाइल–धारक महिला वित्तीय लेन–देन करती है; इंटरनेट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में 17.0% है (IIPS – ICF, 2020, राज्य रिपोर्ट)।

आय और संपत्ति का अभाव: नकद–भुगतान वाला काम 12.6% और संपत्ति–स्वामित्व में गिरावट (तालिका 1)।

निष्कर्ष और नीतिगत सुझाव

निष्कर्ष

- बिहार में अपना खाता उपयोग करने वाली महिलाएँ 26.4% से 76.7% हुईं (+50.3 प्रतिशत अंक); ग्रामीण–शहरी अंतर 2.9 प्रतिशत अंक रह गया।
- एजेंसी के संकेतक मध्यम रूप से सुधरे: निर्णय–भागीदारी +11.3 और मोबाइल +10.5 प्रतिशत अंक; पर केवल 20.6% महिलाओं ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया।
- उपलब्धियाँ नहीं बदलीं: नकद–आय वाला काम 12.5% से 12.6%, संपत्ति–स्वामित्व 58.8% से 55.3%।
- नवादा में खाता 21.4% से 72.3% हुआ, पर वह अब भी निचले पाँच जिलों में है; सूक्ष्म–ऋण उपयोग 10.9% है, जमुई (20.9%) का लगभग आधा।

- जीविका ने बचत, बीमा और समूह–ऋण का ढाँचा बनाया है, पर व्यक्तिगत उद्यम–ऋण बहुत छोटा (2024–25 में 4,453 सदस्य) है।
- NFHS–6 के राष्ट्रीय आँकड़े दिखाते हैं कि खाता 89% होने पर भी निर्णय–भागीदारी 88.7% से 89. 0% ही रही।

इसलिए बिहार में वित्तीय समावेशन का "पहुँच" चरण काफ़ी हद तक पूरा है, और सशक्तिकरण की निर्णायक कड़ी आय–अर्जन और ऋण तक सक्रिय पहुँच है।

नीतिगत सुझाव

- सफलता का पैमाना बदलें: खातों की संख्या के बजाय महिला–खातों में नियमित लेन–देन और निष्क्रिय खातों की दर को जिला–स्तर पर मापा जाए।
- SHG से व्यक्तिगत उद्यम–ऋणः समूह–ऋण के बाद महिला–नेतृत्व वाले व्यक्तिगत उद्यम–वित्त का दायरा बढ़ाया जाए; यही नकद–आय का मार्ग है।
- नवादा में ऋण–उपयोग पर केंद्रित कामः जानकारी (60.0%) और उपयोग (10.9%) के अंतर को पाटने के लिए जमुई और शेखपुरा के जीविका–बैंक संपर्क की कार्य–पद्धति का अध्ययन कर अपनाई जाए।
- डिजिटल क्षमताः मोबाइल उपयोग से आगे बढ़कर महिलाओं को UPI और बैंकिंग–ऐप का सीधा प्रशिक्षण; ग्रामीण महिलाओं (इंटरनेट 17.0%) को प्राथमिकता।
- महिला बैंक–सखी/बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंटः सेवा–बिंदु पर महिलाओं की भागीदारी बढ़े, जिससे दूरी और झिझक कम हो।
- संपत्ति–अधिकारः घर/ज़मीन के स्वामित्व में गिरावट को देखते हुए साझा पंजीकरण को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएँ संपत्ति–आधारित ऋण–पात्रता से जोड़ी जाएँ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) एवं ICF (2020). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5), 2019–20: बिहार राज्य एवं जिला तथ्य–पत्र. मुंबईः IIPS- https%@@rchiips-org@nfhs@NFHS&5&FCTS@COMPENDIUM@Bihar-pdf
2. IIPS- जिलों में महिलाओं के बैंक/बचत खाते के स्वामित्व तथा सूक्ष्म–ऋण की जानकारी और उपयोग के मॉडल–आधारित अनुमान, NFHS–4 व NFHS&5- https%@@iipsindia-ac-in@sites@default@files@Finanacial&inclusion-pdf
3. IIPS एवं ICF. भारत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS–5 2019–21: बिहार (राज्य रिपोर्ट, FR374). https%@@dhsprogram-com@pubs@pdf@FR374@FR374&Bihar-pdf
4. IIPS (2017). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–4), 2015–16: बिहार. मुंबईः IIPS- https%@@www-dhsprogram-com@pubs@pdf@FR338@FR338-BR-pdf
5. विश्व बैंक माइक्रोडेटा लाइब्रेरी. NFHS–4 2015–16, IPUMS उपसमुच्चय, चर C&BANKRESP- https%@@microdata-worldbank-org@catalog@3110@variable@C&BANKRESP
6. राज्य सभा (4 फ़रवरी 2025). अतारांकित प्रश्न 267: प्रधानमंत्री जन–धन योजना. https%@@rsdebate-nic-in@bitstream@123456789@757757@1@PQ&267&04022025&U220&p304&p308-pdf
7. लोक सभा. प्रधानमंत्री जन–धन योजना पर सरकारी उत्तर (चालू खातों का प्रतिशत, अक्टूबर 2024). https%@@eparlib-nic-in@bitstream@123456789@2982267@1@AS11&9pKCAb-pdf
8. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) (27 अगस्त 2025). पीएम जन–धन योजना के 11 वर्ष: बैंकिंग से वंचितों तक बैंक. https%@@static-pib-gov-in@WriteReadData@specificdocs@documents@2025@aug@doc2025827621301-pdf

9. PIB (2026). केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–6 जारी किया. https%@@www-pib-gov-in@PressReleasePage-aspÛ\PRID¾2266600&reg¾3&lang¾1
10. भारत का महावाणिज्य दूतावास, साओ पाउलो (जून 2026). NFHS–6 सारांश. https%@@www-cgisaopaulo-gov-in@wn&26&06&2026&01-php
11. बिहार सरकार. जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी): परिचय. https%@@betastate-bihar-gov-in@jeewika
12. बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (BRLPS) (2016). वार्षिक रिपोर्ट 2015–16. https%@@brlps-in@UplodFiles@Files@Annualþ20Reportþ202015&16-pdf
13. BRLPS/जीविका (2020). 50वीं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (tuojh–ekpZ 2020½- https%@@brlps-in@UplodFiles@Files@50thþ20Quarterlyþ20Progressþ20Reportþ20¼Jan&Marþ202020½-pdf
14. BRLPS (2022). वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022–23. https%@@www-brlps-in@UplodFiles@Files@AAPþ20andþ20Budgetþ20FYþ202022&23-pdf
15. BRLPS/जीविका (2025). 71वीं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (अप्रैल–जून 2025). https%@@brlps-in@UplodFiles@Files@JEEVIKAþ2071stþ20Quarterlyþ20Progressþ20Reportþ20¼April&Juneþ202025½&c-pdf
16. BRLPS/जीविका (2025). 72वीं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (जुलाईदृसितंबर 2025). https%@@brlps-in@UplodFiles@Files@JEEVIKAþ2072ndþ20þ20Quarterlyþ20Progressþ20Reportþ20¼þ20July&Sepþ202025½&c-pdf
17. BRLPS/जीविका (2025). वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25. https%@@www-brlps-in@ UplodFiles@ Files@JEEVIKAþ20Annualþ20reportþ20FYþ202024&25-pdf
18. विश्व बैंक डेटा कैटलॉग. जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना) परिवार सर्वेक्षण. https%@@datacatalog-worldbank-org@search@dataset@0064626
19. विश्व बैंक (2022). ग्लोबल फ़िंडेक्स डेटाबेस 2021: वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और लचीलापन. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक. https%@@www-worldbank-org@en@publication@globalfindeÛ
20. विश्व बैंक ब्लॉग. भारत में महिलाओं की ऋण तक पहुँच में सुधार (Global Finde 2021 पर आधारित). https%@@blogs-worldbank-org@en@allaboutfinance@improving&womens&access&credit&india
21. कुमार, सुनैना (2023). महिलाओं का वित्तीय समावेशनः भारत से वर्तमान साक्ष्य. ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (ORF). https%@@www-orfonline-org@research@financial&inclusion&of&women&current&evidence&from&india
22. विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग (2022). ग्लोबल फ़िंडेक्स 2021: विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग की प्रतिक्रिया. https%@@www-womensworldbanking-org@insights@global&findeÛ&2021&womens&world&banking&response@
23. सेन, अमर्त्य (1999). विकास एक स्वतंत्रता के रूप में (Development as Freedom). ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
24. कबीर, नाइला (1999). संसाधन, एजेंसी, उपलब्धियाँः महिला सशक्तिकरण के मापन पर विचार. डेवलपमेंट एंड चेंज, 30(3), 435–464.
25. स्वैन, आर. बी. एवं वालेंटिन, एफ. वाई. (2009). क्या सूक्ष्म–वित्त महिलाओं को सशक्त बनाता है? भारत में स्वयं सहायता समूहों से साक्ष्य. इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ़ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 23(5), 541–556

❑❑❑